

[Shri Skariah Thomas]

smooth and trouble-free telephonic communications with distant markets. This ultimately affects the development of this area.

Therefore, I would request the Government to convert the present exchange at Pathanapuram into an automatic exchange and thus fulfil the promise given to the subscribers by the telephone authorities five years ago.

- (vii) Need for providing telephones in houses of doctors of safdarjung Hospital who are dealing with Neuro-surgery cases

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सफदर-जंग अस्पताल नई दिल्ली में न्यूरो सर्जरी का एक बहुत महत्वपूर्ण बाई है जहां पर सिर की चोटों व कैंसर का इलाज व आपरेशन होता है। दुर्घटना में लगी सिर की चोटों का तुरन्त इलाज होना जरूरी है। इस अस्पताल में इस बीमारी के इलाज के लिए एक ही महत्वपूर्ण एवं मशहूर डाक्टर रह गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक देश-विदेश में शिक्षा पाये डाक्टरों के यहां टेलीफोन तक की व्यवस्था नहीं है जिस के कारण बहुत से मरीज सीनियर डाक्टर के न जाने के कारण दम तोड़ देते हैं। सफदरजंग के सात डाक्टरों के टेलीफोन लगाने के लिए वित्त मंत्रालय में फाइल पड़ी है, लेकिन आज तक इस मंत्रालय ने सातों डाक्टरों की अपनी इस फाइल पर स्वीकृति नहीं दी है।

इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सफदरजंग अस्पताल के सात डाक्टरों के यहां तुरन्त टेलीफोन लगाने की व्यवस्था की जाय, ताकि भविष्य में मरीजों को तुरन्त व अच्छे

डाक्टर उपलब्ध कराये जा सके और उन के इलाज से मरीजों को जीवन दान मिल सके।

- (viii) Functioning of I.D.P.L. and incident of explosion in its plant at Muza-farpur

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देश में आई० डी० पी० एल० की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। इस उद्योग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को धीरे धीरे समाप्त कर औषधि के मामले में देश को आत्मनिर्भर करना है। लेकिन अफसोस है कि आई० डी० पी० एल० का कार्य संतोषजनक नहीं है।

पिछले 20 नवम्बर 83 को मुजफ्फरपुर आई० डी० पी० एल० प्लांट मुजफ्फरपुर में भयंकर विस्फोट हुआ जिस में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की क्षति हुई। 20 व्यक्ति घायल हुए जिस में 5 व्यक्तियों की स्थिति चिंताजनक है। जिस समय विस्फोट हुआ उस समय कोई मैनेजर वहां मौजूद नहीं थे। प्लांट में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार घायल व्यक्तियों को अविलम्ब मुआवजा दे। प्लांट में सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। आई० डी० पी० एल० के कार्यों की एवं विस्फोट की घटना की जांच करायी जाय।

- (ix) Lay-off in Ideal Dairy Raniwada (Rajasthan) resulting in hardship to poor milk producing farmers

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : मैं नियम

377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व का विषय सदन के समक्ष उपस्थित करता हूँ:

डेरी विकास भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनागत परियोजना है। सरकार की नीति है कि निर्धन ग्रामीणों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आय वृद्धि के लिए डेरी कार्य को एक सहायक उद्योग के रूप में विकसित किया जाय।

ब्राइडियल डेयरी रानीवाड़ा, तहसील भीनमाल, जिला जालौर राजस्थान एक आधुनिक तरीके का बहुत अच्छा संयंत्र है। यह 4-5 करोड़ रुपये की भारी लागत से बनाया गया था। वह भारत सरकार के पशु पालन विभाग के एक सेवा-निवृत्त निदेशक द्वारा एक कम्पनी के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन जब से इस का प्रबंध नई कम्पनी इंडियन होटल कम्पनी लिमिटेड (टाटा ग्रुप) के हाथों में आया है तब से इस डेयरी की दशा दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। प्रबंधकों ने बिना कोई पूर्व सूचना दिये 29-11-83 से ले आफ घोषित कर दिया और इस संयंत्र को अब बन्द करने की तैयारी में हैं। परिणामतः इस संयंत्र के लगभग 150 कर्मचारी बेकार हो जाएंगे। यह अत्यधिक विता का विषय है कि इस के बंद होने से लगभग 1000 वर्ष शिक्षित दूध संग्रहकर्ता और लगभग 70,000 दुग्ध उत्पादक बेरोजगार हो गये हैं। इन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दूध उत्पादक किसान भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये गरीब दूध उत्पादक अपनी आजीविका-उपार्जन की समस्या का सामना कर रहे हैं। जो गायें और भैंसे खरीदने के लिए उन्होंने बैंकों से ऋण लिए

हैं उसे वापस करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि डेरी संयंत्र के मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय। यदि सरकार के विचार से यह कम्पनी इसे सफलतापूर्वक चलाने में असमर्थ हो तो सरकार को इसे टेक ओवर कर के इस डेरी का प्रबंध भारतीय डेरी विकास निगम को सौंप देना चाहिए।

(x) Need for schemes for providing drinking water to desert areas of Rajasthan

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान प्रांत के रेगिस्तान क्षेत्रों में जहां भारत का 55 प्रतिशत रेगिस्तानी क्षेत्र स्थित है, पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं, वे अपर्याप्त हैं। उनसे स्थायी तौर से पीने के पानी की गम्भीर समस्या का निदान नहीं हो रहा है।

मरू क्षेत्र में नलकूप, हैंडपम्प और खुले कुएं खोद कर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनाएं बनाई हैं। परन्तु मरू क्षेत्रों में वर्ष के कम होने से ये योजनाएं कम लाभप्रद साबित हो रही हैं और नलकूपों में पानी का अधिक प्रयोग होने के कारण एवं अधिकांश नलकूपों में कम मात्रा से पानी होने के कारण स्थायी हल का सामान्य नहीं हो सकता है।

राजस्थान नहर ही एक मात्र उक्त समस्या का स्थायी हल है। राजस्थान सरकार ने द्वितीय चरण में पांच संशोधित